राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

वर्ष 13 अंक 2 **जुलाई–दिसम्बर 2011**

1.''राधाकमल मुकर्जी एवं उनके समकालीन :भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक पिता (Founding Fathers)*''–प्रोफेसर टी.एन. मदन, Emeritus professor of Sociology, Institute of Economic Growth, Delhi & Distinguished Senior Fellow, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi. He was elected a Fellow of the Royal Anthropological Institute London and Docteur Honoris Causa by the University of Paris X (Nanterre). In 1995 He occupied the Sarvepalli Radhakrishnan Chair in Humanities and Social Sciences at the University of Hyderabad. He has held visiting appointments at a number of universitites includeing Illinois, Canberra, Paris, Chicago, Washington, Texas, Harvard etc. The Indian Sociological society gave him the Life time Achievement Award in 2008.

प्रस्तुत लेख प्रख्यात समाज–विज्ञानी प्रोफेसर टी.एन. मदन द्वारा 'इंडियन सोशियोलाजीकल सोसायटी' के तत्वावधान में 35 वें अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन कटक में ''राधा कमल मुकर्जी मैमोरियल लेक्चर सीरीज'' के अंग्रेजी में दिये गये उद्घाटन भाषण, जो 'सोशियोलाजीकल बुलेटिन' के वर्ष 60 अंक 1 जनवरी–अप्रैल, 2011 में प्रकाशित हुआ है, का हिन्दी अनुवाद है। लेख के हिन्दी अनुवाद को आदरणीय प्रोफेसर टी. एन. मदन तथा सम्माननीय प्रोफेसर एन. जयराम (प्रबन्ध सम्पादक– सोशियोलाजीकल बुलेटिन) से अनुमति लेकर यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। मूल लेख का हिन्दी में अनुवाद करने का दुरूह कार्य प्रिय डॉ. उमाचरण, वरिष्ठ प्रवक्ता समाजशास्त्र, बरेली कालेज बरेली द्वारा सम्पन्न किया गया है। इस लेख की प्रस्तुति के लिए हम प्रोफेसर टी.एन. मदन, प्रोफेसर एन. जयराम तथा डॉ. उमाचरण तीनों के आभारी हैं।

2.''प्रोफेसर अवधकिशोर सरन – अथ से इति तक''–प्रोफेसर बंशीधर त्रिपाठी,सेवा निवृत्त प्रोफेसर समाजशास्त्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)

समाजशास्त्र के लखनऊ सम्प्रदाय के समाजशास्त्रियों में प्रोफेसर अवध किशोर सरन का नाम अतिशय उल्लेखनीय है। प्रस्तुत आलेख, प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर वंशीधर त्रिपाठी, जो उनके शिष्य भी रहे हैं, द्वारा प्रोफेसर सरन के व्यक्तित्व तथा उनके समाजशास्त्रीय कृतित्व को उजागर करने का एक पॉडित्यपूर्ण प्रयास है।

3.''महिला सशक्तीकरण की सार्थकता में पंचायती राज''–प्रोफेसर अंजलि बहुगुणा,अर्थशास्त्र विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल (उत्तराखण्ड), डा0 पूनम धस्माना, प्रवक्ता (अंशकालिक), अर्थशास्त्र विभाग, हे.न.ब. विश्वविद्यालय, गढ़वाल, (उत्तराखण्ड)

भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण उनके सशक्तीकरण की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम रहा है जिसने महिलाओं को न केवल समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए अपितु ग्रामीण शक्ति संरचना तथा नीति एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में अभिवृद्धि की है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को उजागर करने का एक प्रयास है।

4.'' जनपद चम्पावत में मनरेगा और अनुसूचित जाति वर्ग की प्रतिभागिता''—प्रोफेसर मीना पथनी, परिसर विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड), डा0 रवि जोशी, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड में वैसा तीखा सामाजिक विभेद नहीं है जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य प्रदेशों में है, तथापि यह एक कड़ी सच्चाई है कि उत्तराखण्ड में भी अनुसूचित जाति के अधिकांश व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की मुख्य धारा से वंचित हैं। उनमें से अधिकांश व्यक्ति मजदूरी, रोजगार या अन्य छोटे—मोटे रोजगारों से ही अपनी आजीविका अर्जित करते रहते हैं। उत्तराखण्ड में मनरेगा लागू होने को अनुसूचित जाति वर्ग के समक्ष एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा गया क्योंकि मनरेगा अधिनियम में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे वर्ग को रोजगार सृजन में प्राथमिकता दिये जाने तथा उनकी क्षमता विकास हेतु कई प्रावधान किये गये थे। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जनपद में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिभागिता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

5.'' उद्योगों में अनुसूचित जातीय श्रमिक एवं कार्य संतुष्टि चुनार सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों पर आधारित एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन) ''—डॉ. रामानन्द सिंह,असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चण्डेश्वर, आजमगढ़ (उ.प्र.)

प्रस्तुत शोधपत्र चुनार सीमेंट फैक्ट्री के 100 अनुसूचित जाति के श्रमिकों के जीवन पर आधारित कार्य संतुष्टि का अध्ययन है। फैक्ट्री परिवेश से प्राप्त सुविधाओं के प्रति संतुष्टि, सहभागिता एवं प्रबन्धक का व्यवहार अध्ययन के प्रमुख केन्द्रबिन्दु हैं। आयु, शिक्षा, आरक्षण एवं आय आदि का भी संतुष्टि से गहरा सम्बन्ध है। इस प्रकार इस अध्ययन में यह पाया गया है कि जिन श्रमिकों को सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हैं, वे कार्य के प्रति रूचि रखने के साथ ही अधिक संतुष्टि व्यक्त करते हैं।

6.'' माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का राजनीतिक ज्ञान''—डॉ. जगमोहन सिंह नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड)

समाज की व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे, इस हेतु सफल एवं सक्षम राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक है। राजनीतिक व्यवस्था की सफलता हेतु राजनीतिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही चेतना की सर्वाधिक तर्कसंगत एवं संगठित अभिव्यक्ति होती है और राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में सोचने—समझने की क्षमता, प्रेरणा तथा राजनीतिक सहभागिता की ओर व्यक्ति उन्मुख होता है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्र—छात्राओं के राजनीतिक ज्ञान का अध्ययन किया गया है।

7.'' राजनीतिक भ्रष्टाचार — कारक तथा प्रभाव ''—पवन कुमार वर्मा, शोध अध्येता, समाजशास्त्र, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, (उ0प्र0), प्रोफेसर निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्व प्राचार्य, डी0ए0वी0, पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ (उ0प्र0)

भ्रष्टाचार एक सर्वव्यापी समस्या है, जिससे दुनिया के सभी देश त्रस्त हैं, जिसका सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्रों में विस्तारीकरण हो चुका है। पिछले तीन दशकों में भारत ही नहीं दुनिया के दर्जनों देशों में राजनीति, अपराध और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध खुलकर सामने आये हैं। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत भारतीय समाज में परिव्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारक तथा प्रभावों को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है।

8'' भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्कृति के बदलते प्रतिमान''—डॉ. मनोज कुमार तोमर, व्याख्याता समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.)

भारतीय संस्कृति प्रधानतः एक ग्रामीण संस्कृति है। भारतीय सामाजिक—सांस्कृतिक ढांचे में स्वास्थ्य, रोग व चिकित्सा संबंधी विश्वासों, मूल्यों एवं व्यवहारों का पृथक अस्तित्व नहीं है अपितु वे संपूर्ण संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप इन विचारों एवं मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत ग्रामीण रोगियों के स्वास्थ्य मूल्यों एवं रोग के संबंध में उनकी अभिवृत्तियों तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति की स्वीकारिता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

9.'' लोकतंत्र एवं भारतीय समाज''—डॉ0 ध्रुव भूषण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, घानापुर, चन्दौली (उ.प्र.), डा0 रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान, महात्मा गांधी काशीविद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पर आज यहॉ जन सहभागिता के अभाव से हर स्तर पर भारतीय लोकतांत्रिक शासन—व्यवस्था में गिरावट स्पष्ट हो रही है। लोकतंत्र के स्थान पर कहीं न कहीं सामंतवादिता का स्वरूप उजागर हो रहा है। प्रायः शक्ति, धन, बल व दबाव समूहों इत्यादि की शासन—व्यवस्था में गहरी पैठ बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप नीतियों एवं योजनाओं पर भी इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। आज बड़े पैमाने पर परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध सांप्रतिक भारत की इसी स्थिति को उजागर करने का एक प्रयास रहा है।

10.'' जनगणना 2011 : लिंगानुपात असंतुलन—एक गम्भीर समस्या''—डॉ0 लालिमा सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, एस0एस0 खन्ना गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद (उ.प्र.)

अंग्रेजों के शासनकाल में व्यवस्थित तथा वैधानिक ढंग से पूरे भारत में जनगणना 1881 में की गयी और उसके बाद बिना किसी व्यवधान के प्रत्येक 10 वर्ष के बाद पूरे देश में जनगणना का कार्य सम्पन्न किया जाता रहा है। 130 वर्षों से अधिक के इतिहास में यह विश्वसनीय रहा है और हमेशा इसके आँकड़े सत्य माने गए हैं। जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी और अन्य कई विषयों में विद्वानों और शोधकर्त्ताओं के लिए भारतीय जनगणना के आँकड़े आकर्षक स्रोत रहे हैं। दस वर्ष में एक बार होने वाली जनगणना भारत के लोगों की समृद्ध विविधता का अध्ययन करने और इसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत जनगणना 2011 तथा इसमें उभरती कुछ समस्याओं विशेषतः लिंगानुपात असंतुलन पर प्रकाश डाला गया है।

11.'' ग्रामीण महिलाओं में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता ''—डा. ज्योति गैरोला, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर (उत्तराखण्ड)

भारतवर्ष दुनिया में चीन के बाद सर्वाधिक आबादी वाला देश है, परन्तु निकट भविष्य में हमारे देश के पास सबसे ज्यादा एवं जवान मानव संसाधन विकसित होने की संभावना है जिससे कि भारत को भविष्य में एक सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है। देश में जनसंख्या विस्फोट का होना इसकी प्रगति में बाधक हो सकता है। अतः परिवार नियोजन के प्रति जागरूक एवं दृढ़ संकल्प होना ही समय की पुकार है। भारतीय समाज में महिलाएँ ही परिवार की रीढ़ रही हैं। अतः परिवार नियेाजन के प्रति उनके दृष्टिकोण का अध्ययन इस संदर्भ में समसामयिक होगा। प्रस्तुत लेख उत्तराखण्ड की ग्रामीण महिलाओं में परिवार नियोजन के प्रति अपनाये जा रहे विभिन्न तौर—तरीकों एवं उनके दृष्टिकोण का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

12.'' प्राथमिक शिक्षा में जनजातीय बच्चों की शिक्षा की स्थिति—म.प्र.के संदर्भ में''—डॉ. अनिता धुर्वे, व्याख्याता समाजशास्त्र विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.), रमेश पाल, शोध अध्येता, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म. प्र.)

साक्षरता के आधार पर मध्यप्रदेश को देखें तो अभी भी अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा हुआ है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहां पर अधिकांश क्षेत्रों में जनजातीय सघनता देखी जा सकती है। भारतीय समाज व जनजातियों में, रहन–सहन, भाषा से लेकर आर्थिक व शैक्षणिक सभी में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। यहां के लोगों के विश्वास, मूल्य, प्रथाएँ, आदर्श एवं मान्यताएँ तथा विकास के प्रति दृष्टिकोण अलग–अलग है। भारत में एक ओर ग्रामीण जनजाति है तो शहरी जनजातियां भी बसने लगी हैं। वहीं दूसरी ओर वे जनजातियां जो जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों, दुर्गम स्थानों में निवास करती है जिसकी आजीविका का साधन जंगल है जहां शिक्षा का प्रकाश अभी भी नहीं पहुंचा है। प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय बच्चों की शिक्षा की स्थिति का आकलन करने का एक प्रयास रहा है।

13.'' घरों में काम करने वाली महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन''–डॉ. अनिता धुर्वे,व्याख्याता समाजशास्त्र विभाग, बरकतउल्ला विश्वविधालय, भोपाल (म.प्र.), कु. मंजूलता नागरे, शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, बरकतउल्ला विश्वविधालय, भोपाल (म.प्र.)

पुरूष प्रधान, भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को कार्य की प्रकृति, पद के अधिकार एवं कर्तव्य तथा उनकी शारीरिक क्षमताओं के नाम पर हेय दृष्टि से देखा जाना और हर क्षेत्र में उनका शोषण एक आम बात है। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की उपज घरेलू कामकाजी महिला वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। प्रस्तुत लेख मध्य प्रदेश के भोपाल नगर की घरेलू कामकाजी महिलाओं की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा उनकी कार्य की दशाओं के अध्ययन पर आधारित है।

14.'' लिंगानुपात का समाजशास्त्रीय पक्ष''–मीताश्री श्रीवास्तव, शोध अध्येत्री, मानवविज्ञान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.)

प्रस्तुत शोध प्रपत्र वर्ष 2011 के भारतीय जनगणना विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। प्रपत्र के पहले भाग में सामान्य लिंगानुपात तथा शिशु लिंगानुपात सम्बन्धी सैद्धान्तिक बिन्दुओं पर चर्चा की गई है। आंकड़ों के आधार पर यह दर्शाया गया है कि आर्थिकी, शिक्षा एवं जातिगत व्यवस्था सदैव महिला शिशु की भाग्य रेखा नहीं बदल सकती है। दूसरे भाग में उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति पर चर्चा करते हुये यह बताया गया है कि घटते हुए लिंगानुपात को किस प्रकार रोका जाये ताकि भावी जनसंख्या सुदृढ़ हो।

15.'' संवैधानिक व वैधानिक अधिकार–हिन्दू महिलाओं के सशक्तीकरण के विशेष संदर्भ में ''–सुश्री अचला सोनकर, प्रवक्ता इतिहास विभाग, दयानंद गर्ल्स (पी.जी.) कालेज, कानपुर (उ.प्र.)

भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किये गये ताकि वह अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ ही राष्ट्र के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सके। चूँकि महिलाएं राष्ट्र की जनसंख्या का लगभग आधा भाग हैं और किसी भी राष्ट्र की उन्नति का मानक उस देश में महिलाओं की स्थिति द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतः संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान करने के साथ ही, उनकी शारीरिक भिन्नता और सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए महिलाओं हेतु कुछ विशेष कानून बनाने का अधिकार भी राज्य को दिया गया है। इन संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों द्वारा कानूनी रूप से तो महिलाओं को समता का अधिकार प्राप्त हो गया है। परन्तु जब वास्तविकता और व्यवहारिकता की बात होती है तब महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तथ्य की पुष्टि हमारी न्याय व्यवस्था से सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा भी की गई है। प्रस्तुत लेख इन्हीं बिन्दुओं पर प्रकाश डालेगा का एक प्रयास है।

16.'' सामाजिक नवनिर्माण एवं शिक्षा का स्ववित्तपोषीकरण''—डॉ0 लालचन्द्र शर्मा, रीडर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र, पी0एस0एम0(पी0जी0) कालेज, कन्नौज (उ.प्र.)

सम्प्रति भारतवर्ष में शिक्षण पद्धति का नवीन अर्थबोध– स्ववित्तपोषीकरण, निजीकरण, व्यवसायीकरण एवं भूमण्डलीकरण जैसे शब्दों के चक्रव्यूह में उलझ गया है। शिक्षा के स्ववित्तपोषीकरण ने सरकार को शिक्षा के दायित्व से कुछ हद तक मुक्त तो किया है लेकिन निजी संस्थानों को शिक्षा को व्यवसाय बनाने की छूट भी दे दी है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का इसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। शिक्षा के केन्द्र डिग्रियां बांटने वाली या अंक बेंचने वाली दुकाने बन गये हैं।प्रस्तुत आलेख सांप्रत भारत में शिक्षा के स्ववित्तपोषीकरण की स्थिति, इससे उत्पन्न प्रवृत्तियों एवं शिक्षकों की समस्याओं को उजागर करने का एक प्रयास है।

17.'' गांधी दर्शन एवं सर्वोदय : व्यक्ति एवं समाज की प्राथमिकताओं का विश्लेषण''—हेमराज मीणा, ए.सी.पी., राजस्थान पुलिस सेवा, जयपुर (राज.), डॉ. कान्ता, मीणा , व्याख्याता समाजशास्त्र, कानुरिया महाविद्यालय, जयपुर (राज.)

'सर्वोदय' शब्द गांधी जी का दिया हुआ है। इसमें 'सर्वभूत हितेरताः' की भारतीय कल्पना, सुकरात की सत्य साधना, बाइबिल से प्रभावित, रस्किन की अन्तयोदय की अवधारणा एक साथ समन्वित है। गांधी जी की सर्वोदय समाज एक जीवन दर्शन ही नहीं, अपितु ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, सौंदर्य मीमांसा की संभावनाओं से परिपूर्ण एक समग्र दर्शन के रूप में उपस्थित है। प्रस्तुत लेख गांधी जी का सर्वोदय की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या का एक प्रयास कहा जा सकता है।

18.'' बाल श्रमिकों की समाजार्थिक एवं शैक्षणिक समस्याएं''—डॉ. आरती सिंह, प्रवक्ता समाजकार्य विभाग, श्री अटल बिहारी बाजपेयी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

बाल श्रम सांप्रत समाज की गंभीर समस्याओं में से एक वैश्विक समस्या है। प्रत्येक बालक को भोजन, शिक्षा, खेल, स्नेह पाना उसका नैसर्गिक तथा मानवाधिकार है किन्तु बाल श्रमिकों को अपेक्षित मात्रा में इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भारत में बाल श्रम की स्थिति और भी भयावह है। प्रस्तुत आलेख मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत बाल श्रमिकों की समाजार्थिक एवं शैक्षणिक समस्याओं को प्रकाशित करने का एक प्रयास रहा है।

19.'' उत्तराखण्ड की महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता''—सुबोध भण्डारी, शोध अध्येता, राजनीतिक विज्ञान विभाग, हे.न.ब.ग. विश्वविद्यालय श्रीनगर (उत्तराखण्ड), डॉ0 सुमनलता, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान विभाग, हे.न.ब.ग. विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उत्तराखण्ड)

मानवाधिकारों के प्रति निरंतर बढ़ती हुई जागरूकता के चलते 21वीं सदी को मानवाधिकारों की सदी कहा जा सकता है। यों तो भारत में भी मानवाधिकार का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है किन्तु देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं के संदर्भ में इस पर प्रश्नचिन्ह अवश्य लग जाता है। महिलाओं में भी यदि पहाड़ की महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात किया जाय तो स्थिति और भी चिन्तनीय दिखाई पड़ती है। प्रस्तुत आलेख में, चमोली जनपद के विशेष संदर्भ में, उत्तराखण्ड की महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का आकलन किया गया है।

20.'' ग्रामीण महिला सशक्तीकरण में सूक्ष्म वित्त की भूमिका ''—मुकेश सूर्यवंशी, शोध अध्येता अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्लया विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

संपूर्ण विश्व में सूक्ष्म वित्त व्यवस्था को महिला निर्धनता उन्मूलन के एक सवल विकासात्मक आधार के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म वित्त संस्था ग्रामीणों को व्यक्तिगत उपभोग उत्पादन अथवा व्यवसाय हेतु वित्त

प्रदान करती है। देश में 1980 के बाद सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विस्तार एवं विकास हुआ है। प्रस्तुत लेख ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में सूक्ष्म वित्त की भूमिका को उजागर करने का एक प्रयास है।

21.'' आधुनिक भारत पर मार्क्सवादी इतिहास लेखन''—डॉ. राजेश कुमार दलाल, शोध छात्र, नीमस विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

भारतीय इतिहास के मार्क्सवादी स्कूल का अभिप्राय इतिहासकारों के उस समूह से है जो इतिहास लेखन का आधार मुख्यतः मार्क्सवादी इतिहास दर्शन एवं पद्धति को मानते हैं। किन्तु मार्क्सवादी स्कूल के भारतीय इतिहासकार केवल कार्ल मार्क्स के इतिहास दर्शन का ही अनुसरण करते हैं न कि माकर्स द्वारा कही गई प्रत्येक बात का। वस्तुतः वे भारतीय इतिहास के संबंध में मार्क्स के अनेक निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करते। प्रस्तुत लेख आधुनिक भारत पर मार्क्सवादी इतिहास लेखन का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

22.'' गाँधी दर्शन में सत्याग्रह का सिद्धान्त''—डॉ0 बन्दना चमोली, प्रवक्ता दर्शनशास्त्र विभाग हे0न0ब0ग0 विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

गाँधी जी की सत्याग्रह की धारणा में तीन तत्व निहित हैं– सत्य, अहिंसा और आत्मपीड़ा। सत्याग्रह में सत्य के तत्व व्यक्ति को नैतिक मानवतावाद की ओर अहिंसा का तत्व त्याग और समाजसेवा की ओर और आत्मपीड़ा उसे बड़े से बड़ा त्याग करने की ओर प्रेरित करता है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत की विशद् व्याख्या की गई है।

23.'' जनगणना में जाति ''—डा0 रश्मि, वरिष्ठ प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, विद्यावती मुकन्द लाल महिला महाविद्यालय, गाजियाबाद (उ.प्र.), डा0 मीना शुक्ला, रीडर, समाजशास्त्र विभाग, विद्यावती मुकन्द लाल महिला महाविद्यालय, गाजियाबाद (उ.प्र.)

निस्संदेह भारतीय समाज में जाति की अहम् भूमिका है, हिन्दू धर्म का तो आधार ही जाति है। जातियों की पहचान उनके पैतृक व्यवसायों के आधार पर न केवल स्पष्ट श्रम विभाजन को प्रस्तुत करती रही है अपितु जाति के कठोर नियमों ने रक्त की शुद्धता को भी बनाये रखा तथा जाति के कार्यात्मक विभाजन ने व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने में योगदान दिया। धीरे–धीरे जाति की विकृतियों ने इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में ला खड़ा किया, जिसके परिणामस्वरूप, सर्वविदित है, इसका सबसे वीभत्स रूप भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। जाति में जनगणना का समर्थन कर रहे विभिन्न राजनीतिक दल वोट–बैंक की राजनीति कर अपना हित साधने के प्रयास में जुटे हैं। जातिवार जनगणना, संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार और भेदभाव दूर करने वाली आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध है।

उदारवाद व वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पूरे विश्व–समाजों को समेट दिया है जहाँ मानवीय मूल्य व अधिकार और स्वतन्त्रता का महत्त्व और अधिक हो जाता है। हमारे सामने व्यक्ति की स्वतन्त्रता का इतना बड़ा दृश्य है कि उसमें कोई जातिगत पंचायत हमारे भाग्य की नियन्ता नहीं हो सकती। इसलिए आज जनगणना के लिए जाति को आधार बनाना बेमानी ही नहीं, समाज को सैकड़ों साल पीछे ले जाने जैसा होगा। प्रस्तुत लेख इसी स्थिति को विश्लेषण करने का एक प्रयास रहा है।

24.'' शिक्षा एवं साहित्य के विकास में रुहेला शासकों का योगदान''—डा0 समन ज़हरा ज़ैदी, इतिहास विभाग, म0ज्यो0फूले,रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

ऐतिहासिक तथ्यों के पुनरावलोकन से यह स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि जिन शासकों ने शिक्षा एवं साहित्य में रूचि प्रदर्शित की है उनके शासन काल में शिक्षा एवं साहित्य का तीव्र गति से विकास हुआ है। प्रस्तुत शोध आलेख रूहेलखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत रूहेला शासन काल में शिक्षा एवं साहित्य के विकास में रूहेला शासकों के योगदान को प्रकाशित करने का एक प्रयास रहा है।

25.'' समाजवादी चिन्तक के रूप में स्वामी विवेकानन्द''—अभिषेक रंजन, शोध अध्येता राजनीतिविज्ञान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, जयप्रकाश नरायण, आचार्य नरेन्द्र देव, राम मनोहर लोहिया आदि महान समाजवादी विचारकों से बहुत पहले स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूं। स्वामी जी का हृदय दरिद्रों के प्रति असीम संवेदना से भरा हुआ था। इसलिए जनसाधारण का उत्थान उनके कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग था। उन्होंने स्पष्टतः कहा था कि जनसाधारण के उत्थान के बिना भारत का पुनरूत्थान संभव नहीं। इसलिए उन्होंने समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया। उनका सामाजिक समानता का सिद्धांत तत्वतः समाजवादी है, किन्तु वह समाजवाद को आदर्श व्यवस्था नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूं कि वह एक पूर्ण व्यवस्था है अपितु इसलिए कि आधी रोटी 'कुछ नहीं' से भली है। प्रस्तुत लेख एक समाजवादी चिन्तक के रूप में स्वामी विवेकानन्द के विचारों को प्रस्तुत करता है।

26.'' अनुसूचित जातीय महिलाओं में शिक्षा के संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता''—सोनिया नाग, शोध अध्येत्री, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हो रहा है। स्वतंत्रता के समय महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 8.86 था जबकि वर्तमान में 65.46 प्रतिशत हो गया है। अगर महिलायें शिक्षित हों तो सामाजिक स्थिति को भी सुधारा जा सकता है क्योंकि समाज में हो रहे भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह आदि बुराईयों से महिलायें शिक्षित हुये बिना नहीं लड़ सकतीं। महिलाओं का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। अनुसूचित जाति वर्ग तथा महिलायें प्राचीन काल से ही शोषित रही हैं। गन्दी बस्तियों में रहीं इन महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना अति आवश्यक है। प्रस्तुत शोध लेख भोपाल नगर की झुग्गी बस्ती में निवास करने वाली अनुसूचित जातीय महिलाओं में शिक्षा के संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता के अध्ययन पर आधारित है।

27.'' गढ़वाल हिमालय के भेड़पालक समुदाय का सामाजिक अध्ययन''—डॉ0 सोना पैन्यूली, मानवविज्ञान विभाग, हे.न.ब.ग. विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

आज कारण चाहे अशिक्षा का रहा हो या इन दूर– दराज के ग्रामीण पहाड़ी एवं सीमान्त क्षेत्र के पिछड़ेपन का रहा हो, लेकिन इतना अवश्य है कि जहां आज बदलते परिवेश में विकास की दौड़ तथा उन्नति के मार्ग पर भारत के अन्य जिले अगरोत्तर वृद्धि की राह पर हैं, वहीं टिहरी जनपद का यह क्षेत्र आज भी सबसे अधिक पिछड़ी श्रेणी में है जो एक अतिशयोक्ति नहीं है। प्रस्तुत लेख गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत टिहरी जनपद गांव के भेड़पालक समुदाय के सामाजिक जीवन को उजागर करने का एक प्रयास है।

28.'' उत्तराखण्ड की जनजातियों में बुक्सा जनजाति की शिक्षा का समाजशास्त्रीय विवेचन''—बालक राम राजवंशी, शोध अध्येता, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, हे.नं.ब.ग. विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल, (उत्तराखण्ड)

जनजातियां समाज का सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग हैं जो सदियों से समाजार्थिक दृष्टि से शोषण एवं भेदभाव के शिकार रहे हैं। इनकी निम्न स्थिति के कारणों में अशिक्षा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रोपरांत सरकार द्वारा उनकी शैक्षिक स्थिति उन्नत करने हेतु अनेकानेक प्रयास किये जाते रहे हैं। अतः वर्तमान में उनकी शैक्षिक स्थिति जानने की दिशा में प्रस्तुत लेख उत्तराखण्ड की बुक्सा जनजाति की शिक्षा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का एक प्रयास कहा जा सकता है।

29.'' वाल्मीकि का जन्म तथा समय''—सुश्री सन्तोष, शोध अध्येत्री, संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के 'आदिकवि' और 'आदि काव्य रामायण' के रचयिता के रूप में विश्वविख्यात हैं। महान संत वाल्मीकि द्वारा विरचित रामकथा महाकाव्य एवं उनकी शिक्षा हिन्दू संस्कृति की गौरवशाली धरोहर है जो समाज को सदैव प्रेरित करती रहेगी। वाल्मीकि का यह अनुपम महाकाव्य अनेक महान काव्यों का प्रेरणा स्त्रोत बना है। प्रस्तुत आलेख उन्हीं प्रख्यात संत वाल्मीकि के जन्म एवं समय के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्ति की दिशा में एक प्रयास है।

30.'' गर्भवती महिलाओं में विशेष डिजाइन के वस्त्रों के प्रति जागरूकता का अध्ययन''—पारूल चौधरी, शोध अध्येत्री, गृह विज्ञान, एन.के.बी.एम.जी. स्नातकोत्तर कालेज चन्दौसी, मुरादाबाद (उ.प्र.)

महिलाओं के जीवन में गर्भावस्था का समय अतिशय सुखद एवं महत्वपूर्ण होता है किन्तु इस दौरान उन्हें कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस विशेष समय में शरीर के बढ़ते हुए आकार के कारण पूर्व के बने वस्त्र पहनना असंभव सा हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था के लिए विशेषतः बनाये गये रूपांकित वस्त्र ढीले एवं आरामदायक होते हैं और आकार में सामान्य वस्त्रों से बड़े होते हैं— यही गर्भावस्था के वस्त्र कहलाते हैं। प्रस्तुत आलेख मुरादाबाद नगर में गर्भावस्था के वस्त्रों के प्रति महिलाओं में जागरूकता के अध्ययन पर आधारित है।

31. पुस्तक समीक्षा—पुस्तक : बालश्रम – जनजातीय शोषण के सामाजिक—आर्थिक आयाम, लेखिका : डॉ0 कान्ता मीणा, व्याख्याता समाजशास्त्र, कानुरिया महाविद्यालय, जयपुर (राज.), समीक्षक— प्रोफेसर एस.एल. शर्मा, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)